



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229544  
CG-DL-E-10092021-229544

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943

No. 260]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

मामला सं. एडी(ओआई)-13/2021

**विषय :** चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

**फा. सं. 6/13/2021-डीजीटीआर.**—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” अथवा एडी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार चंदन स्टील लिमिटेड, ट्यूबासेक्स प्रकाश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वेलस्पन स्पेशलिटी सोल्यूशन लिमिटेड (जिन्हें यहां आवेदक भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भारी क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए अनुरोध किया है।

#### क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद 6 इंच तक के और उस के सहित डायमीटर के स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स हैं, चाहे उनका विनिर्माण हॉट एक्सट्रूजन प्रक्रिया या हॉट पियरसिंग प्रक्रिया का प्रयोग करके किया गया हो और चाहे उनकी बिक्री हॉट फिनिश या कोल्ड फिनिश पाइप्स और ट्यूब्स के रूप में की गई हो, जिनमें डिफेक्टिव, नॉन प्राइम या सैंकेंडरी ग्रेड के रूप में आयातित संबद्ध वस्तुएं भी शामिल हैं।
4. स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स का प्रयोग संरचनात्मक प्रयोजनों और तरल पदार्थों व गैसों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग गैस और ईंधन से संबंधित अनुप्रयोगों, पेट्रोकेमिकल और रिफायनरीज, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर और थर्मल पावर सहित विद्युत जेनेरेटर्स और एयरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों में किया जाता है।
5. विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण या तो हॉट एक्सट्रूजन प्रक्रिया अथवा हॉट पियरसिंग प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है जिसे क्रॉस रोल पियरसर प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में दोनों प्रक्रियाओं का प्रयोग कर विनिर्मित किए गए उत्पाद शामिल हैं।
6. विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ शीर्ष 7304 के तहत अध्याय 73 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

#### ख. समान वस्तु

7. आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन जन.गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

#### ग. घरेलू उद्योग की स्थिति

8. यह आवेदन चंदन स्टील लिमिटेड, ट्यूबासेक्स प्रकाश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वेलस्पन स्पेशिएलिटी सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदन का समर्थन रत्नमणि मेटल्स और ट्यूब लि. द्वारा किया गया है। आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, वे भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
9. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख समानुपात के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा, आवेदक समर्थक सहित भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन के 67 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और उचित जांच के पश्चात, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) के संदर्भ में आवेदक पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन ऊपर नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

#### घ. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

10. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ-7 के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए कोरिया गणराज्य की उपयुक्त तीसरे देश के रूप में पहचान की है। उपयुक्त तीसरे देश में संबद्ध वस्तुओं की कीमत के संबंध में सूचना की अनुपलब्धता के कारण, आवेदकों ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भारत को कोरिया गणराज्य से निर्यातों की कीमत पर भरोसा किया है।

11. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य से भारत को निर्यातों की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

#### **ड. निर्यात कीमत**

12. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का निर्धारण वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए, संबद्ध वस्तुओं की सीआईएफ कीमत पर विचार के द्वारा निर्धारण किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्ययों और कारखानागत निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए बैंक प्रभारों के कारण किये गये हैं।

#### **च. पाटन मार्जिन**

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखानागत स्तर पर तुलना की गई है। इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं कि चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखानागत निर्यात कीमत से महत्वपूर्ण रूप से अधिक है जो प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि भारतीय बाजार में संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही हैं और पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है, जो जांच की शुरुआत को न्याय संगत ठहराता है।

#### **छ. क्षति और कारणात्मक संबंध**

14. घरेलू उद्योग की क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने कथित पाटन के परिणाम स्वरूप हो रही क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग की कीमतों की कीमत कटौती और कीमत ह्रास हुआ। आवेदकों का दावा है कि जहां कोविड-19 के कारण आयातों की मात्रा और घरेलू उद्योग की क्षमता विस्तार में गिरावट आई है और उत्पादन के संबंध में उनके निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, निम्न बाजार हिस्से, लाभों, नकद लाभों और निवेशों पर आय में ह्रास हुआ है। इसके अलावा, वेलस्पन स्पेशिएलिटी सोल्यूशन लि. ने दावा किया है कि संबद्ध आयातों ने भारत में कंपनी की स्थापना को महत्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाया है और कंपनी देश में अपने उत्पादों के लिए लाभप्रद बाजार को ढूंढने में असमर्थ है। पाटनरोधी जांच की शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही उल्लेखनीय क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

#### **ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

15. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए, जो यदि लगाया जाता तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

#### **झ. संबद्ध देश**

16. वर्तमान पाटनरोधी जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

#### **ञ. जांच की अवधि**

17. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 (12 महीने) प्रस्तुत की है। क्षति जांच अवधि को 2017-18, 2018-19, 2019-20 और पीओआई की अवधि के रूप में विचारित किया गया है।

#### **ट. प्रक्रिया**

18. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा।

**ठ. सूचना को प्रस्तुत करना**

19. कोविड महामारी से उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों को मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।
20. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**ड. समय-सीमा**

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि उक्त नियमावली के स्पष्टीकरण की शर्त में, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाला नोटिस उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा जिसको यह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या निर्यातक देशों से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को संप्रेषित किया गया था। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

**ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. “गोपनीय” या “अगोपनीय” अनुरोध पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशिकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि,

आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. नियमावली के नियम 6(7) के संदर्भ में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ को शामिल करने वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। सार्वजनिक फाइल को "इलैक्ट्रॉनिक मोड में" अनुरक्षित करने के तरीकों को तैयार किया जा रहा है।

#### त. असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)  
**INITIATION NOTIFICATION**  
New Delhi, the 10th September, 2021  
**Case No. AD (OI) - 13/2021**

**Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Stainless-Steel Seamless Tubes & Pipes originating in or exported from China PR.**

**F. No. 6/13/2021-DGTR.**—Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules or AD Rules"), Chandan Steel Limited, Tubacex Prakash India Private Limited and Welspun Specialty Solutions Limited (hereinafter referred to as the "Applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of anti-dumping investigation concerning the imports of "Stainless-steel seamless tubes & pipes" (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. The applicants have alleged that material injury to the domestic industry is being caused due to the dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country. Accordingly, the applicants have requested for the imposition of the anti-dumping duty on the import of the subject goods originating in or exported from the subject country.

**A. Product under consideration**

3. The product under consideration is stainless-steel seamless tubes and pipes with diameter up to and including 6 inches, whether manufactured using hot extrusion process or hot piercing process and whether sold as hot finished or cold finished pipes and tubes, including subject goods imported in the form of defectives, non-prime or secondary grades.
4. Stainless-steel seamless tubes and pipes are used for structural purposes and to transfer liquids and gases. The product under consideration is used in application relating to oil and gas; petrochemicals and refineries; atomic energy; power generators including nuclear and thermal power; and aerospace and defence applications.
5. The product under consideration can be manufactured using either hot extrusion process or hot piercing process, which is also known as cross roll piercer process. The scope of product under consideration includes product manufactured using both processes.
6. The product under consideration is classified under Chapter 73 under tariff headings 7304. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

**B. Like article**

7. The applicants have claimed that there are no known significant differences in the subject goods produced by the domestic industry and that exported from China PR. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The applicants claim that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of proposed investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated by the Authority as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

**C. Domestic industry and standing**

8. The application has been filed by Chandan Steel Limited, Tubacex Prakash India Private Limited and Welspun Specialty Solutions Limited. The application is supported by Ratnamani Metals & Tubes Limited. The applicants have claimed that they have neither imported the subject goods from the subject country during the period of investigation nor are they related to any exporter or the producer of the subject goods in the subject country or to an importer of the subject goods in India.
9. As per evidence available on record, the applicants account for a major proportion in the domestic production of the like article in India. Further, the applicants together with supporter account for 67% of the total domestic production of the like article in India. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the applicants constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

**D. Normal value for China PR**

10. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Paragraph 7 of Annexure-I to the Rules. The applicants have identified Korea RP as an appropriate third country to determine the normal value for China PR. Due to unavailability of information regarding the price of the subject goods in the appropriate third country, the applicants have relied on the price of the exports from Korea RP to India for determination of the normal value.
11. For the purpose of the present investigation, the Authority has considered the normal value based on the price of exports from Korea RP to India.

**E. Export price**

12. The export price of the subject goods has been determined by considering the CIF price of the subject goods, as reported in the DGCIS data. The price adjustments have been made on account of ocean freight, inland freight, marine insurance, commission, port expenses and bank charges to arrive at ex-factory export price.



**F. Dumping margin**

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in China PR is significantly higher than the ex-factory export price indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject country into the Indian market and the dumping margin is above de-minimis level so as to justify the initiation of investigation.

**G. Injury and Causal link**

14. The information furnished by the applicants have been considered for assessment of the injury to the domestic industry. The applicants have furnished prima facie evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping, resulting in price undercutting and price suppression of the prices of domestic industry. The applicants have claimed that while the volume of the imports have declined due to Covid-19 and the capacity expansion of the domestic industry, their performance has been adversely impacted in respect of the production, the low market share, deterioration in the profits, the cash profits and the return on investments. Further, Welspun Specialty Solutions Limited has claimed that the subject imports have materially retarded the establishment of the company in India and the company is unable to find a viable market for its products in the country. There is sufficient prima facie evidence of the material injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject country to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

**H. Initiation of Anti-Dumping Investigation**

15. On the basis of the duly substantiated application by and on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates the investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of the anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**I. Subject country**

16. The subject country involved in the present anti-dumping investigation is China PR.

**J. Period of investigation**

17. The applicant has proposed the period from 1st April, 2020 to 31st March, 2021 (12 months). The injury investigation period has been considered as the period 2017-18, 2018-19, 2019-2020 and the POI.

**K. Procedure**

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

**L. Submission of Information**

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Authority via email at the email addresses [adg15-dgtr@gov.in](mailto:adg15-dgtr@gov.in), [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in), [dir16-dgtr@gov.in](mailto:dir16-dgtr@gov.in) and [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in).
20. The known producers/exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be connected with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time-limit set out below.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

**M. Time Limit**

23. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be to the Authority via email at the email addresses [adg15-dgtr@gov.in](mailto:adg15-dgtr@gov.in), [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in), [dir16-dgtr@gov.in](mailto:dir16-dgtr@gov.in) and [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the time limit mentioned above.

**N. Submission of information on confidential basis**

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
27. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.



**O. Inspection of Public File**

33. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

**P. Non-cooperation**

34. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. and Designated Authority